खंड १५ नंबर १ जनवरी २०१६

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

'सतत विकास लक्ष्यों' के लिए दक्षिण एशिया एकजुट

एसडीजी पर दक्षिण एशिया फोरम के विचार–विमर्श के दौरान प्रतिष्ठित पैनलिस्ट।

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र एस्कैप और नीति आयोग के साथ साझेदारी में 4-5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्यों पर दक्षिण एशिया फोरम - सतत विकास पर एशिया–प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) के लिए उप-क्षेत्रीय तैयारी बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य वर्ष 2019 के आरंभ में बैंकॉक में आयोजित होने वाले सतत विकास पर छठे एशिया–प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) के लिए उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण और संबंधित जानकारियां प्रदान करना था। इस दिशा में आगे की कार्यवाही के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडे को लागू करने में हासिल उपलब्धियों की समीक्षा करने की दृष्टि से प्रमुख प्लेटफॉर्म होने के नाते एपीएफएसडी दरअसल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा दोनों के ही संदर्भ में सतत विकास पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) की तैयारियों में आवश्यक सहयोग देता है।

शेष पृष्ठ 7 पर जारी.....

'एसएसीईपीएस' ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं के द्वार खोलने पर नीतिगत संवाद की मेज़बानी की

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र एस्कैप और दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस) के साथ साझेदारी में 6 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करनेः आगे की राह' के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं के द्वार खोलने पर नीतिगत संवाद का आयोजन किया।

शेष पृष्ठ 7 पर जारी.....

नीतिगत संवाद के प्रमुख प्रतिभागी।

प्रभाव आकलन और विकास प्रभावशीलता पर विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम)

एफआईडीसी ने 'सदर्न वॉयस', ढाका के सहयोग से 5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'प्रभाव आकलन, विकास प्रभावशीलता और मापः एसडीजी के युग में उभरते नीतिगत विकल्प' पर एक विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम) का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और प्रोफेसर मुस्तफिजुर रहमान, प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), ढाका के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. देबाप्रिया भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित फेलो, सीपीडी

राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

और चेयर, सदर्न वॉयस ने मुख्य प्रस्तुति दी। इसके बाद खुली चर्चा आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

'नेस्ट' का पेरिस शांति फोरम में प्रतिनिधित्व

11 से 13 नवंबर, 2018 तक आयोजित पेरिस शांति फोरम (पीपीएफ) ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाई और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए टिकाऊ शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गवर्नेंस से जुड़ी हस्तियों को एकजुट किया। यह फोरम तीन ठिकानों पर कार्य करता है जहां वाद–विवाद, समाधान और नवाचार सामने लाए जाते हैं। समाधानों के लिए संबंधित ठिकाने पर कुल मिलाकर 121 वैश्विक गवर्नेंस परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया जिनमें से 10 परियोजनाओं को एक वर्ष तक विशेष सहायता के लिए चुना गया।

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट), आरआईएस को एक वैश्विक गवर्नेंस परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। दक्षिण यानी विकासशील देशों के लिए और दक्षिण की ओर से एक सहयोगी पहल 'नेस्ट' मुख्य रूप से एक थिंक टैंक और शैक्षणिक फोरम है जो दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) के क्षेत्र में नीतिगत जानकारियां उपलब्ध कराता है।

'नेस्ट' दक्षिणीय सहयोग के तहत विकास परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन पर भी गौर करता है। पीपीएफ में भाग

राजदूत मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस पेरिस शांति फोरम में श्री प्रणय सिन्हा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस के साथ।

लेने की प्रेरणा ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण)' में अंतर्निहित एकजुटता की विशेषता 'एसएससी के मूल्यों से उभरती है। यह समावेशी विकास सहयोग के लिए पहली आवश्यकता है जो वैश्विक गवर्नेंस और टिकाऊ शांति का आधार है। इसका मूर्त रूप होने के नाते नेस्ट और पीपीएफ सामूहिक रूप से सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत एक बिल्कुल उपयुक्त साझेदारी को दर्शाते हैं।

पीपीएफ में नेस्ट का प्रतिनिधित्व आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने किया जिन्होंने श्री प्रणय सिन्हा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस और डॉ. एंड्रे डी मेलो ई सूजा, कोऑर्डेनाडोर डी इंटरकाम्बियो ई को–ऑपेराकाओ इंटनेशिअनल (क्वायंट), डायरेटोरिया डी एस्टुडॉस ई रिलैकोस इकोनोमिकास ई पॉलिटिकैस इंटरनेशिअनल्स (डीआईएनटीई), इंस्टीट्यूटो डी पेसक्विसा इकोनोमिका एप्ली काडा (आईपीईए), ब्राजील के साथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

'एक्ट ईस्ट' और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नीतिगत संवाद

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के सहयोग से 28 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'एक्ट ईस्ट' और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नीतिगत संवाद का आयोजन किया। स्वागत भाषण सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर), भारत सरकार द्वारा दिया गया। श्री राम मुइवा, सचिव, एनईसी और श्री रवि कपूर, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुवाहाटी ने उद्घाटन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिए। मुख्य भाषण भारत में थाईलैंड के राजदूत माननीय श्री चुटिनटॉर्न गांगसाकडी द्वारा दिया गया, तथा श्री नवीन वर्मा, सचिव, डोनर ने उद्घाटन भाषण दिया।

बाएं से दाएं: श्री रवि कपूर, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुवाहाटी; श्री राम मुइवा, सचिव, एनईसी; श्री नवीन वर्मा, सचिव, डोनर मंत्रालय; सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, डोनर मंत्रालय; डॉ. प्रबीर डे, आरआईएस स्थित एआईसी; भारत में थाईलैंड के राजदूत माननीय श्री चुटिनटॉर्न गांगसाकडी।

आरआईएस स्थित एआईसी में प्रोफेसर डॉ. प्रबीर डे ने 'एक्ट ईस्ट' और 'दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक एकीकरण' पर मुख्य प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति के बाद पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी पड़ोस के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों, इसकी चुनौतियों और आगे की राह पर एक पैनल परिचर्चा हुई। सत्र की अध्यक्षता डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग ने की। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के भारतीय निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने विशेष भाषण दिया। इस सत्र के पैनल सदस्यों में ये शामिल थे : श्री एम.पी.बेजबरुआ, पूर्व सदस्य, एनईसी एवं भारत सरकार के सचिव (पर्यटन); सुश्री प्रिया माथुर, सलाहकार, विश्व बैंक; राजदूत गौतम मुखोपाध्याय, म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत; डॉ. प्रियरंजन सिंह, प्रोफेसर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल; डॉ. गुरुदास दास, प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिल्चर; और श्री सब्यसाची दत्ता, निदेशक, एशियन कॉन्फ्लूएन्स, शिलांग। आखिर में समापन सत्र में श्री बिमान दत्ता, सदस्य, एनईसी द्वारा समापन भाषण दिया गया, तथा सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच साझेदारीः उभरती रूपरेखा

संबंधित श्रृंखला में 28वां ब्रेकफास्ट सेमिनार 24 अक्टूबर, 2018 को आरआईएस में 'भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच साझेदारीः उभरती रूपरेखा को समझना' विषय पर आयोजित किया गया। राजदूत विवेक काटजू ने इस सत्र की अध्यक्षता की। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस इसमें प्रमुख वक्ता थे। अंत में आयोजित की गई परिचर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

28वें ब्रेकफास्ट सेमिनार में मुख्य वक्ता राजदूत अमर सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजदूत विवेक काटजू के साथ।

वैश्विक व्यापार प्रणाली का संरक्षण और बहुपक्षवाद की भूमिका

आरआईएस जापान के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक शोध कार्यरत रहा है। आरआईएस ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) पर काफी काम किया है। इस पहल की भूरि–भूरि प्रशंसा प्रधानमंत्री ने गत वर्ष 2017 में अहमदाबाद में एएफडीबी की वार्षिक बैठक के दौरान की थी। आरआईएस ने एएजीसी की अवधारणा को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए आठ परिचर्चा पत्र प्रस्तुत किए हैं। जापानी संस्थानों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए आरआईएस ने जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ) के साथ साझेदारी में 22-23 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एशिया–प्रशांत फोरम की बैठक की सह–मेजबानी की।

जेईएफ जनहित से जुड़ा एक फाउंडेशन है जिसकी देख–रेख जापानी कैबिनेट कार्यालय द्वारा की जाती है। श्री कजुमासा कुसाका इसके मौजूदा चेयरमैन और सीईओ हैं। वर्ष 1985 में अपनी स्थापना के समय से ही जेईएफ अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर हर वर्ष इस आयोजन की सह–मेजबानी करता रहा है जिसका उद्देश्य आर्थिक और तकनीकी आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जापान एवं अन्य देशों

सुश्री प्रीति सरन, भूतपूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय एशिया–प्रशांत फोरम 2018 में सभी प्रतिष्ठित पैनल

के बीच आपसी समझ को और ज्यादा बढ़ाना है। विगत वर्षों के दौरान इसने एशिया, अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलन आयोजित किए हैं।

'एपीएफ 2018' के मुख्य कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर 2018 को 'वैश्विक व्यापार प्रणाली का संरक्षण और बहुपक्षवाद की भूमिका' थीम पर इसके द्वारा सार्वजनिक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके अंतगर्त तीन पैनल ट्रेडिंग सत्र आयोजित किए गए जिस दौरान व्यापार एवं नई प्रौद्योगिकी; क्षेत्रीय एकीकरण के लिए अनिवार्यताएं: सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी का महत्व एवं भूमिका: एसडीजी की प्राप्ति के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सार्वजनिक संगोष्ठी को एशिया–प्रशांत क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने संबोधित किया जिनमें कई भारतीय विशेषज्ञ भी शामिल थे। सार्वजनिक संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक), राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निवासी राजनयिकों, सेवारत और उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारियों ने शिरकत की। सार्वजनिक संगोष्ठी में मुख्य भाषण सुश्री प्रीति सरन, भूतपूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया। सार्वजनिक संगोष्ठी के बाद 23 नवंबर 2018 को महानिदेशक, आरआईएस एवं अध्यक्ष, जेईएफ की अगुवाई में एपीएफ के सदस्यों के साथ गोपनीय मंत्रणा की गई।

जी–20 पर परिचर्चा सत्र

हाल ही में जी–20 शिखर सम्मेलन से उभर कर सामने आए मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आरआईएस ने 12 दिसंबर, 2018 को 'जी–20 पर परिचर्चा सत्र' का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और फिर उन्होंने चर्चाओं की शुरुआत की। श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने बैठक की अध्यक्षता की। बाद में डॉ. रजत कथूरिया, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय जी–20 पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए।

'रिवार्ड प्रोजेक्ट' पर बैठक

आरआईएस यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' में एक साझेदार संस्थान है। वर्ष 2014 में शुरू हुई परियोजना वर्ष 2019 में समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना के एक घटक के रूप में वित्त पोषण करने वाली एजेंसी ने 'सूचना विज्ञान और गैर–चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मचारियों का उपयोग करके केरल में हृदय रोग की द्वितीयक रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रणाली सीखना (एलएचएससीवीडी)' पर अध्ययन को मंजूरी दी है। यह एक वर्ष के लिए है।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' की बैठक में स्वागत भाषण देते हुए।

अध्ययन की समीक्षा करने के लिए 16 दिसंबर 2018 को केरल के कुमारकोम में इस परियोजना पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। प्रोफेसर थॉमस पोगे, दर्शन शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के लीटनर प्रोफेसर, येल विश्वविद्यालय; डॉ. मिल्टोस लादिका, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर ने 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' पर प्रस्तुति दी। डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने एक प्रस्तुति दी। इसके बाद 'केरल अध्ययन एवं अब तक हुई प्रगति व अगले कदम और प्रदेय उत्पादों (डिलिवरेबल्स)' पर एक प्रस्तुति डॉ. जयदीप सी मेनन, प्रमुख, निवारक कार्डियोलॉजी, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने दी। यही नहीं, डॉ. मिल्टोस लादिका, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर ने 'जीनोम एडिटिंग में व्यापक रुझानः चीन से उभरते अनुभव' विषय पर डिनर के दौरान व्याख्यान भी दिया। प्रोफेसर थॉमस पोगे, दर्शन शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के लीटनर प्रोफेसर, येल विश्वविद्यालय और डॉ. वसंत मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप महानिदेशक, आईसीएमआर एवं अध्यक्ष, एफईआरसीआई (भारत में आचारनीति समीक्षा समितियों के लिए फोरम) इस अवसर पर प्रतिभागी थे।

दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन

दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र विकास सहयोग से जुड़ी ऐसी कई पहलों के साक्षी रहे हैं जो न्यायसंगत विकास, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और कारोबार करने में आसानी जैसे उद्देश्यों पर केंद्रित हैं। इस क्षेत्र का विशिष्ट बहुपक्षवाद उन व्यापक आर्थिक विकास एजेंडों को सुविधाजनक बनाने वाले प्लेटफार्मों के अभ्युदय में परिणत हुआ है जिन्हें विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता दी गई है। बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल) और बहु–क्षेत्रवार तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) जैसे प्लेटफॉर्म स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रभाव डालने और सीमा पार आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय रूपरेखा विकसित करने की दृष्टि से अब व्यवहार्य या उपयोगी मंच बनते जा रहे हैं। इसी तरह की तर्ज पर दक्षिण एशिया के साथ आसियान के बढ़ते संबंधों को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और व्यापार आधिपत्य का मुकाबला करने की आर्थिक विवशता से बल मिल रहा है। विकास संकेतकों को कारगर ढंग से लक्षित करने के लिए उन संस्थानों के साथ नीतिगत सामंजस्य और समावेशी सहयोग सुनिश्चित करने की जरूरत है जो एक सुदृढ़ एवं उपयोगी सहयोगात्मक रूपरेखा तैयार करने में अत्यंत अहम साबित हो सकते हैं। बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में विकास संबंधी सहयोग सिविल सोसायटी की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) और एफआईडीसी ने दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र के प्रमुख सिविल सोसायटी संगठनों के साथ मिलकर 17–18 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन' का आयोजन किया। इसका उद्देश्य, इन समूहों के लक्ष्यों के साथ–साथ समूचे एशिया के सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा ज्ञान एवं डेटा के पारस्परिक आदान–प्रदान के जरिए दक्षिण एशिया के विकास सहयोग पर करीबी नजर रखने के तरीकों पर एक जीवंत संवाद सुनिश्चित करना था। सम्मेलन का आयोजन दो प्रारूपों में किया गया। 17 दिसंबर 2018 को भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों को भारत के विकास सहयोग की वैश्विक मौजूदगी से अवगत कराया गया और 18 दिसंबर 2018 को 'दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन' में भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीएसओ की भागीदारी के लिए निवेदन किया गया।

भारत और वियतनाम पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग

वियतनाम अत्यंत लंबे समय से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है। यह सद्भावना एवं विश्वास हमारे बहुआयामी और बहु–क्षेत्रवार सहयोग में परिलक्षित होता है। यह सहयोग कई मुद्दों पर आधारित है जिसमें रक्षा और हिफाजत; व्यापार एवं वाणिज्य; विज्ञान और तकनीक; क्षमता निर्माण; स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों का पारस्परिक आदान–प्रदान; और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय फोरम शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में और अधिक तालमेल का पता लगाना आवश्यक है।

आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक 'भारत और वियतनाम में पारंपरिक चिकित्सा' पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए।

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आरआईएस और एफआईटीएम ने वियतनाम के दूतावास के सहयोग से नई दिल्ली में 10 दिसंबर, 2018 को 'भारत और वियतनाम में पारंपरिक चिकित्सा' पर आधे दिन का सम्मेलन आयोजित किया। आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण और सुश्री ट्रान क्विन्ह हयोंग, निदेशक, वियतनाम पत्रकारिता एवं सोशल मीडिया संस्थान के आरंभिक भाषण के साथ हुआ। भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री फाम सान्ह चाऊ ने विशेष भाषण दिया।

एसटीआईपी व्याख्यान श्रृंखला

	वक्ता	विषय
	M,- lquh dkj&iMjlu सलाहकार, अनुसंधान एवं नवाचार / उप–प्रमुख, नवाचार केन्द्र, डेनमार्क का दूतावास, भारत, और lqJh rkfu;k ÝkbMfjp भारत के लिए आरएंडआई सलाहकार और भारत के लिए यूरोपीय संघ का भूटान प्रतिनिधिमंडल	foKku] çkS|kfxdh vkSj fodkl ds fy, uokpkj% foKku dwVuhfr dh Hkwfedk 31 अक्टूबर 2018
	Jh jtuh jatu jf'e प्रतिष्ठित फेलो, पृथ्वी विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, टेरी, और M,- uojkst ds- nqck'k सीनियर फेलो, नीतिगत अनुसंधान केंद्र और समन्वयक, जलवायु पहल	vkÃihlhlh dh 1-5 fMxzh fjiksVZ vkSj isfjl le>kSrs dk Hkfo";% foKku ,oa tyok;q ifjorZu dh jktuhfr ij cgl 13 नवंबर 2018
	çks- gSyu y,dgM निर्मित पर्यावरण के संकाय के डीन, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया	T;knk fVdkÅ 'kgjksa dh vksj 12 दिसंबर 2018

अर्थशास्त्र की छात्राओं के साथ संवाद

दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमन की अर्थशास्त्र की छात्राओं के साथ एक संवादात्मक सत्र 24 अक्टूबर, 2018 को आरआईएस में आयोजित किया गया।

इस संवादात्मक सत्र में 20 से भी अधिक छात्राओं ने भाग लिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'अनुसंधान एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाः असमानता और एसडीजी' के क्षेत्र में आरआईएस से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत किया। डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर ने 'अंतरराष्ट्रीय व्यापारः सिद्धांतों' पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. सब्यसाची साहा ने नीतिगत विकल्पों एवं व्यापार, प्रौद्योगिकी और रोजगार पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्राओं के साथ आरआईएस में संबोधित करते हुए।

'सतत विकास लक्ष्यों' के लिए दक्षिण एशिया एकजुट
पृष्ठ 1 से जारी.....

फोरम का शुभारंभ डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए); प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस); श्री यूरी अफानासीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक, भारत और डॉ.इस्माइल रहीमी, माननीय उप अर्थव्यवस्था मंत्री, अफगानिस्तान के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। डॉ. पुष्पा राज कदेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत ने उद्घाटन भाषण दिया।

बैठक में दौरान इन विषयों पर सत्र आयोजित किए गएः दक्षिण एशिया में 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीएफ 2019 के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीएफ 2019 के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा : कार्य समूहों द्वारा कार्य प्रगति के बारे में सूचना देना एवं आगे की राह; 2019 में एपीएफएसडी और एचएलपीएफ की थीम 'लोगों का सशक्तिकरण और समावेशन एवं समानता सुनिश्चित करने' पर उप क्षेत्रीय दृष्टिकोण; दक्षिण एशिया में एसडीजी के कार्यान्वयन के साधनः वित्त, प्रौद्योगिकी, और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना (एसडीजी 17); दक्षिण एशिया में एसडीजी के कार्यान्वयन के साधनः संकेतक, डेटा, आंकड़े एवं आगे की कार्यवाही तथा समीक्षा (एसडीजी 17); एसडीजी की प्राप्ति में तेजी के लिए क्षेत्रीय सहयोग; संपन्नं करना और समापन सत्रः आगे की राह। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में विचार–विमर्श में भाग लिया।

'एसएसीईपीएस' ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग.....
पृष्ठ 1 से जारी.....

डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए); राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार, चेयरमैन, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस); प्रो. दीपक नैय्यर, सह–अध्यक्ष, दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस) ने आरंभिक भाषण दिए। श्री रजनीश, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया और माननीया डॉ. पुष्पा राज कदेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

संवाद के दौरान इन विषयों पर सत्र आयोजित किए गए: उभरते वैश्विक रुझानों की पृष्ठभूमि में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए संभावनाएं और चुनौतियां; परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी की संभावनाएं एवं चुनौतियां; कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में क्षेत्रीय सहयोग; दक्षिण एशिया में एसडीजी की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के बीच सहयोग पर गोलमेज बैठक; और संपन्न करना एवं समापन सत्र। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के प्रतिनिधियों ने विचार–विमर्श में भाग लिया।

दक्षिणीय सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

'दक्षिणीय सहयोग के बारे में जानना' विषय पर आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरआईएस में 12–23 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री एम. सी. अरोड़ा, आरआईएस के परिचयात्मक सत्र के साथ हुआ। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक ए. डिमरी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। 21 देशों के 29 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विकास सहयोग के कुछ उदाहरण प्रतिभागियों के समक्ष पेश करने के अलावा इस कार्यक्रम में दक्षिणीय सहयोग की सैद्धांतिक रूपरेखा, एसएससी के लिए वैश्विक स्वरूप; भारत के विकास सहयोग; एसएससी के लिए वर्तमान वैश्विक मुद्दों से जुड़े मॉड्यूल को कवर किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने तकनीकी सत्रों और सामूहिक चर्चाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने विचार–विमर्श करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने इसके साथ ही स्थिति पत्र (स्टैटस पेपर) भी पेश किए जिनमें क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भों और देश के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। इन्हें *'दक्षिणीय सहयोगः अनुभव और चुनौतियां'* नामक एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया गया।

'दक्षिणीय सहयोग के बारे में जानने' पर आयोजित आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ।

आरआईएस में प्रतिनिधिमंडल/आगंतुकों की अगवानी

- श्री हांग जू हैम, प्रभारी अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप और श्री राजन सुदेश रत्न, आर्थिक मामलों के अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 अक्टूबर, 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च (आईआरएसईएम) के प्रतिनिधिमंडल ने 30 अक्टूबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया जिसमें डॉ. जीन–बैप्टिस्ट जीनजेनविल्मर, निदेशक, आईआरएसईएम और श्री सोफी गौथियर, काउंसलर (राजनीति), नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास शामिल थे।
- सामाजिक प्रभाव पर ईकेएचओएस, अर्जेंटीना के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया। इस संगठन का उद्देश्य लैटिन अमेरिका और भारत के बीच पुलों का निर्माण करना है।
- वैले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने 23 अक्टूबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया जिसमें श्री पाउलो बर्गमैन, कंट्री हेड; श्री रेनन क्युरी, एस्ट्राटेजिया ई नोवोस नेगोसियॉस, वैले, एस.ए.; श्री अमित मल्होत्रा, प्रभागीय प्रबंधक, वैले; और सुश्री नीता गुलगानी शामिल थे।
- सुश्री नंदिता बरुआ, देश प्रतिनिधि, द एशिया फाउंडेशन ने 26 अक्टूबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- जॉर्जिया के राजदूत माननीय श्री अर्चिल दजुलियाशविल्ली ने 26 अक्टूबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- विदेश में समकालीन भारत और इसकी विरासत के बारे में जागरूकता एवं समझ बढ़ाने के लिए विदेश प्रचार प्रभाग (एक्सपीडी) ने संपर्क कार्यक्रम चलाया, श्रीलंका के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 20 वरिष्ठ पत्रकारों/संपादकों ने 27 नवंबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- श्री रेमी मारेचाक्स, अफ्रीका एवं हिंद महासागर के लिए निदेशक, यूरोप और विदेश मामलों का मंत्रालय, फ्रांस गणराज्य, श्री निकोलस दासनोई, निदेशक के सलाहकार और श्री क्लेयर थुआउडेट, मिशन के उप प्रमुख, नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास ने 11 दिसंबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- श्री डेविड कात्रुद, क्षेत्रीय निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, बैंकॉक; डॉ. हमीद नुरू, कंट्री डायरेक्टर, डब्ल्यूएफपी इंडिया और सुश्री प्रदन्या पैठाणकर, एसडीजी मैनेजर, डब्ल्यूएफपी इंडिया ने 12 दिसंबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।
- विदेश में समकालीन भारत और इसकी विरासत के बारे में जागरूकता एवं समझ बढ़ाने के लिए विदेश प्रचार प्रभाग (एक्सपीडी) ने संपर्क कार्यक्रम चलाया, चीन के पत्रकारों/संपादकों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक परिचय कार्यक्रम के लिए 20 दिसंबर 2018 को आरआईएस का दौरा किया।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सविन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 9 अक्टूबर 2018 को चीन के बीजिंग में 'विकास के लिए चीनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी' द्वारा 'चीन और विदेश में आरआरआईः एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'बड़े विकासशील देश में आरआरआईः भारत में ताजा स्थिति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत द्वारा संयुक्त रूप से 'चिकित्सा उत्पादों तक पहुंचः एसडीजी 2030 को प्राप्त करना' पर आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन में 'औषधीय उत्पादों तक पहुंच के लिए साझेदारीः द्विपक्षीय संधियां और क्षेत्रीय समझौतेः एसडीजी पर फोकस' पर एक प्रस्तुति दी।
- 29 अक्टूबर 2018 को बैंकॉक में एशियाई विकास बैंक द्वारा 'एडीबी की मसौदा आरसीआई परिचालन योजना (2019–2030) और व्यापार प्रस्तुतियों' पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया।
- 5 नवंबर 2018 को पटना में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय और ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'क्षेत्रीय विकास के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा' पर विशेष व्याख्यान दिया।
- 13 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन और म्यांमार के दूतावास द्वारा म्यांमार दिवस पर म्यांमार और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर 'एक्ट ईस्टः इसे कारगर बनाना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 16 नवंबर 2018 को हरियाणा में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा कृषि एवं सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त रूप से आयोजित 26वें एईआरए वार्षिक सम्मेलन में 'कृषि और एसडीजीः वैश्विक नीति में सामंजस्य, अनिवार्यताएं और नई रणनीतियां' विषय पर डॉ. जी के चड्ढा स्मारक व्याख्यान दिया।
- 20 नवंबर 2018 को ढाका में नीतिगत संवाद केंद्र द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशिया के लिए एसडीजी की व्याख्या करनाः एक क्षेत्रीय रूपरेखा की तलाश में' के दौरान 'एसडीजीः उभरते भारतीय अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 30 नवंबर 2018 को बैंकॉक में आईएफपीआरआई और डब्ल्यूएफपी द्वारा 'एशिया–प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी 2 की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय शून्य भूख रणनीतिक समीक्षाओं का उपयोग करना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित एक अलग कार्यक्रम में पैनलिस्ट थे।
- 4–5 दिसंबर 2018 को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), टोक्यो द्वारा टी–20 के लिए आयोजित टोक्यो आरंभिक बैठक में 'एसडीजी और निजी क्षेत्र' पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 दिसंबर 2018 को बेंगलुरू में तारुण्य शिक्षण सेवा ट्रस्ट, बेंगलुरू द्वारा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 'भारत में स्वास्थ्य परंपराओं के समूह पर जिग्नासा आरोग्य मेला और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में 'आयुर्वेद के वैश्वीकरण की संभावनाएं और चुनौतियां–अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य' पर मुख्य भाषण दिया।
- 13 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में अमेजन डिजिटल उत्सव में भारतीय सूक्ष्म एवं लघु और मझोले उद्यम संघ (फिस्मे') द्वारा 'विश्व के लिए मेक इन इंडिया' पर संयुक्त रूप से आयोजित पैनल परिचर्चा में पैनलिस्ट थे।
- 15 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) के 101वें वार्षिक सम्मेलन में 'कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाः प्रौद्योगिकी एवं व्यापार से लाभ उठाना' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- 21 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बैठक में 'डीबीटी – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित तीसरे भारत–चीन थिंक–टैंक फोरम में 'विकास योजनाओं का विश्लेषण करने' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 31 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूह 4' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 9 नवंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूहः 1 (नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन रूपरेखा)' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 23–27 नवंबर, 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित 'प्रथम भारत–रूस रणनीतिक संवाद' में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 30 नवंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्री नीति' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. टी.सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्रवर्तन पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया और इसके साथ ही 6 अक्टूबर, 2018 को पारंपरिक/स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण एवं कृषि उत्पादों व पौधों की किस्मों के संरक्षण पर प्रस्तुतियां दीं।
- 22 अक्टूबर, 2018 को जोहान्सबर्ग में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की दिशा में नवाचार एवं ज्ञान साझा करने पर आयोजित ब्रिक्स संगोष्ठी में भाग लिया और 'ब्रिक्स में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर', 'यूएचसी की दिशा में नवाचार एवं ज्ञान साझा करना' और 'आगे की राह' पर प्रस्तुतियां दीं।
- 1 और 2 नवंबर, 2018 को बीजिंग में आयोजित 'ब्रिक्स देशों में पारंपरिक चिकित्सा सहयोग को बढ़ावा देने और मानव स्वास्थ्य के समुदाय का निर्माण करने पर 2018 ब्रिक्स थिंक–टैंक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' में भाग लिया तथा 'स्वस्थ शहर के निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर प्रस्तुति दी।
- 14-17 नवंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा फोरम

में भाग लिया और 'भारत में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण का अर्थशास्त्रः विपणन रणनीतियां एवं ब्रांड निर्माण' पर अपने विचार व्यक्त किए।

- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरू द्वारा 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में एक 'संसाधन विशेषज्ञ' के रूप में भाग लिया और इसके साथ ही 19 नवंबर, 2018 को 'बौद्धिक संपदा अधिकारः राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य (पीसीटी)' पर एक सत्र का संचालन किया।
- 30 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित आसियान नवाचार शिखर सम्मेलन में 'व्यावहारिक अनुभव और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की ओर से प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के लिए चुनौतियां' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ द्वारा पंजाब के अधिकारियों के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक 'संसाधन विशेषज्ञ' के रूप में भाग लिया और इसके साथ ही 3 दिसंबर, 2018 को 'सामाजिक सतत विकास लक्ष्य – अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली (एसडीजी–3) की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 दिसंबर, 2018 को टीआईएफएसी और डीआरडीओ द्वारा आईपीआर पर आयोजित उन्नत कार्यशाला के दौरान 'साहित्यिक कृतियों के संरक्षण, सॉफ्टवेयर, डिजिटल माध्यम और प्रचलित प्रथाओं में उचित उपयोग के प्रावधान' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. पी के आनन्द

विजिटिंग फेलो

- 30 अक्टूबर 2018 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों के बीच पारस्परिक संवाद के जरिए 'एसडीजी के स्थानीयकरण और अच्छी प्रथाओं का मानदंड तय करने' पर आयोजित उच्चस्तरीय परामर्श में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 2-4 नवंबर, 2018 के दौरान त्रिपुरा को एक समृद्ध राज्य बनाने पर अगरतला में आयोजित 'चिंतन शिबिर' में भाग लिया और सिफारिशें पेश कीं।
- 6 दिसंबर 2018 को नए महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा 'सतत विकास लक्ष्यों' पर आयोजित संगोष्ठी में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2018 को गुवाहाटी में 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की दूसरी बैठक में भाग लिया और सुझाव दिए।
- 17-18 दिसंबर 2018 के दौरान नई दिल्ली स्थित भारत इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र में दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के अग्रणी सिविल सोसायटी संगठनों की सहभागिता वाले 'वाणी' द्वारा एफआईडीसी और आरआईएस के सहयोग से आयोजित 'साउथ–साउथ सिविल सोसाइटी कॉन्क्लेव' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 21-22 दिसंबर 2018 को इटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'एसडीजी के स्थानीयकरण' पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और इसके साथ ही एक सत्र की अध्यक्षता भी की।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

सलाहकार

- 9 अक्टूबर 2018 को बीजिंग में 'कास्टेड' द्वारा आयोजित 'चीन और विदेश में आरआरआईः एक अंतरराष्ट्रीय संवाद' के दौरान 'बड़े विकासशील देश में आरआरआईः भारत में ताजा स्थिति' पर प्रो. सचिन चतुर्वेदी के साथ मिलकर एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2018 को इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज, वियना में आयोजित 'न्यू होराइजन कंसोर्टियम बैठक' के दौरान 'आरआरआईः भारत की ओर से परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 अक्टूबर 2018 को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, वियना में 'विज्ञान कूटनीति आजः चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 4 दिसंबर 2018 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित 'होराइजन 2020 सूचना दिवस' पर 'होराइजन 2020 और ईआरसी का वित्त पोषणः अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 18 दिसंबर, 2018 को आईडीएसए, नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियांः सहयोग के लिए एजेंडा' पर आयोजित 11वें दक्षिण एशिया सम्मेलन के दौरान 'प्रौद्योगिकी, सरकार एवं मानव सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- 2–4 नवंबर, 2018 के दौरान त्रिपुरा को एक समृद्ध राज्य बनाने पर अगरतला में आयोजित 'चिंतन शिबिर' में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2018 को गुवाहाटी में 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की दूसरी बैठक में भाग लिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 4–5 दिसंबर 2018 को टोक्यो, जापान में आयोजित 'टी20 जापान 2019 आरंभिक सम्मेलन' में भाग लिया। व्यापार, निवेश और वैश्वीकरण पर गठित कार्य बल के सदस्य के रूप में चयनित किए गए।

थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

प्रजादीपोक संस्थान ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 तक 'कार्यकारी अधिकारियों के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीति और गवर्नेंस' शीर्षक से भारत का एक अध्ययन दौरा आयोजित किया। आरआईएस स्थित एआईसी ने 26 नवंबर को प्रवासी भारतीय केंद्र (पीबीएल), नई दिल्ली में '21वीं सदी में भारत का आर्थिक रूपांतरण' विषय पर आगंतुक प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद का आयोजन किया। थाईलैंड के 60 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रो. सूरत होराइचाकुल, निदेशक, भारत अध्ययन केंद्र, चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक इस प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे। आरआईएस स्थित एआईसी में प्रोफेसर डॉ. प्रबीर डे ने इस परिचर्चा की अगुवाई की जिन्होंने 'एक्ट ईस्ट' नीति और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर एक प्रस्तुति दी।

fjikVZ

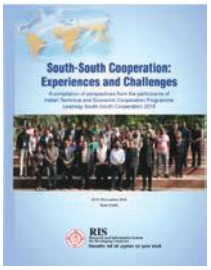

nf{k.k & nf{k.k lg;kx% vuHko vkj pukfr;k
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

vkjvkÃ,l dk ifjppk i=

\# 235 D;k Hkkjr vrjjk"Vh; 0;kikj dk fy, fMftVy –f"V l r;kj g\ द्वारा रश्मि बंगा

\# 234 Hkkjr e ,lMhth dk fy, ofpkfjd :ijs[kk vkj fuxjkuh 0;oLFkk fodfl r djuk द्वारा कृष्ण कुमार और पी.के. आनंद

vkjvkÃ,l dh uhfrxr lkj i=

\# 86 gYFk flVh dk ckjs e ;ktuk cukuk vkj ikjifjd fpfdRlk% vrjjk"Vh; vuHkok l lh[kuk द्वारा प्रो. टी.सी. जेम्स

\# 85 vkjlhÃih ij mHkjrh xfr'khyrk द्वारा वी.एस. शेषाद्रि

\# 84 vkjlhÃih% D;k vkj dl द्वारा राजीव खेर

\# 83 vkjvkjvkÃ% ,d Hkkjrh; ifjç{; (अंग्रेजी)

\# 82 vkjvkjvkÃ% ,d Hkkjrh; ifjç{; (हिंदी)

fodkl lg;kx leh{kk ¼Mhlhvkj½

[kM 1 l[;k 7] vDVcj 2018

lkmFk ,f'k;k bdku,fed tuy

[kM 19] l[;k 2 ¼tykÃ &fnlcj 2018½

,QvkÃVh,e dk Ldçix iij

\# 2 Hkkjr e ikjifjd Kku dk lj{k.k] vDVcj 2018

,f'k;kÃ tko çk|kfxdh fodkl leh{kk ¼,chMhvkj½

[kM 20 l[;k 1 ,o 2 ekp] tykÃ 2018

vkjvkbZ,l ldk; }kjk cká çdk'kuk e ;kxnku

चतुर्वेदी, सचिन 2018. 'ब्लू इकॉनोमी' , बिबेक देबरॉय, अनिर्बन गांगुली और किशोर देसाई (संपादक), *मोदी सरकार के दौर में नए भारत का निर्माणः बदलाव* / नई दिल्लीः विस्डम ट्री।

चतुर्वेदी, सचिन और चक्रबर्ती, मिलिंदो। 2018. बीएपीए का स्मरण करना और आगे की राह, *स्पैनिश जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन,* संख्या 43।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए कनेक्टिविटी 2.0' , पारस खरेल (संपादक), *दक्षिण एशियाई सहयोगः नए और पुराने मुद्दे,* 'सावटी', काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'हिंद–प्रशांत सहयोगः कनेक्टिविटी पर कुछ विचार' लतिन मानसिंह, अनूप के. मुद्गल और उदय भानु सिंह (संपादक), पूरबसाः *पूरब का पूरब से समागमः हिंद–प्रशांत के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी भारत के बीच तालमेल बैठाना,* पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशिया में आर्थिक गलियारों को विकसित करनाः प्राथमिकताएं और आगे की जिम्मेदारी', सार्क सचिवालय में (संपादित), *दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए अगले कदमः क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर एक अध्ययन,* काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए व्यापार में सुविधा के उपाय', सार्क सचिवालय में (संपादित), *दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए अगले कदमः क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर एक अध्ययन,* काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'बीसीआईएम आर्थिक गलियारा और पूर्वोत्तर भारतः समावेशी विकास एजेंडे की आवश्यकता', गुरुदास दास और सी. जोशुआ थॉमस (संपादक), *बीसीआईएम आर्थिक सहयोगः भू–अर्थशास्त्र और भू–राजनीति का पारस्परिक प्रभाव,* रूटलेज, नई दिल्ली।

जेम्स, टी. सी. 2018. आईपीआर में 'जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट एवं मानवाधिकार' और *'पारंपरिक ज्ञान, टीकेडीएल एवं मानवाधिकार' और भारत पर विशेष जोर के साथ मानवाधिकार* द्वारा मनोज कुमार सिन्हा और जुपी गोगोई (संपादक), भारतीय विधि संस्थान।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:

facebook www.facebook.com/risindia

twitter @RIS_NewDelhi

YouTube www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादकः तीश मल्होत्रा

‘राष्ट्रीय समुद्री नीति’ की ओर भारत अग्रसर

Mk , l- d- ekgrh
ikQlj] vkjvkb, l

वर्तमान में भारत एक समग्र समुद्री वाणिज्यिक परिवेश विकसित करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री नीति तैयार करने में जुटा हुआ है। इस समय जारी बहस में विशेष जोर राष्ट्र की विशाल क्षमता का व्यापक आकलन करने के साथ–साथ संभावित आंतरिक एवं बाह्य तालमेल स्थापित करने पर है जो समुद्री व्यापार को समावेशी और सतत विकास का इंजन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि प्रभावकारी तटीय क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों और मल्टी–मोडल परिवहन प्रणालियों को एकीकृत किया जाए, जिससे कि भारत के विदेश व्यापार को काफी बढ़ावा मिल सके और इसके साथ ही देश को समुद्री क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में विशाल समुद्री तट और विविध क्षेत्रों (सेक्टर) वाला प्रमुख समुद्री राष्ट्र है। दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य–पूर्व एवं दक्षिण एशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के देशों तक फैले हिंद महासागर रिम के देशों के साथ अत्यंत मजबूत ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंध स्थापित कर चुके भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी या देश माना जाता है। भारत और हिंद महासागर के अन्य तटीय देशों एवं दुनिया के अन्य भागों के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार अतीत में काफी तेजी से बढ़ा है। वैसे तो भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान समुद्री व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, लेकिन समग्र अर्थों में समुद्री वाणिज्य के रुझानों और स्वरूप के बारे में शायद ही कोई जानकारी है जिसमें समुद्री व्यापार और समुद्री वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे कि कच्चे एवं प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पादों; समुद्री जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, दवाओं इत्यादि का निर्यात एवं आयात; तटों, समुद्री तटों, इत्यादि पर पर्यटकों का आगमन; और अन्य समुद्री वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल हैं। सूचनाओं में इस खाई को पाटने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री नीति में समुद्री वाणिज्य पर एक विशेष खंड समर्पित किया गया है जिसके अंतर्गत देश में समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों (सेक्टर) और उप–क्षेत्रों की संपूर्ण श्रृंखला को शामिल किया गया है।

भारत बहुत लंबे समय से कई उत्पादों और सेवाओं के समुद्री वाणिज्य में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री नीति के संदर्भ में समुद्री वाणिज्य नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी), क्षेत्रीय समुद्री संपर्क (कनेक्टिविटी) और बंदरगाह सेवाओं, तटीय शिपिंग, समुद्री वित्त एवं बीमा, समुद्री कर्मियों से जुड़ी सेवाओं, समुद्री कानूनी सेवायें, समुद्री प्रमाणन एवं परामर्श सेवाओं, समुद्री बचाव सेवाओं, माल ढुलाई अग्रेषण (फ्रेट फॉरवर्डिंग), कार्गो संचालन सहित कई समुद्री सेवायें शामिल हैं। मत्स्य पालन को छोड़ नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में व्यापार मौजूदा समय में एक अपारदर्शी क्षेत्र है। विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की कुछ बिखरी हुई सूचनाओं के अलावा, आधुनिक सांख्यिकीय प्रणालियों के अनुसार एक अलग श्रेणी के रूप में निर्यात और आयात का कोई भी व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं है। नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टरों के अंतर्गत व्यापार किए गए उत्पादों से संबंधित आंकड़ों के अभाव में व्यापार नीति जटिल बन गई है क्योंकि शुल्क दरों और गैर–शुल्क बाधाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों के अभाव के अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का व्यापार भारत के लिए लाभदायक है या नहीं।

भारत में वस्तुओं की ही तरह समुद्री सेवाओं के व्यापार पर भी यही बातें लागू होती हैं। ज्यादातर सेवा क्षेत्रों के मामले में भारत को प्रभावित करने वाले सबसे स्पष्ट कारणों में उपयुक्त भौतिक बुनियादी ढांचे का अभाव, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (एप्लीकेशंस) की अपर्याप्त पैठ या पहुंच, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, समुद्री प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभाव, समुद्री कौशल के प्रमाणन में मानकीकरण की कमी और अन्य नियम–कायदे शामिल हैं। उदाहरण के लिए, शिपयार्डों को कलपुर्जों की आपूर्ति करने में ढिलाई शिपिंग कंपनियों को कोलंबो पोर्ट से जहाज मरम्मत सेवाओं को बाहर से आयोजित करने पर विवश करती है। चिंता का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय शिपिंग परियोजनाओं का वित्तपोषण है। शिपिंग फाइनेंस को काफी जोखिम भरा माना जाता है जिससे बैंक इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से हिचकिचाते हैं। समुद्री सम्पर्क भी समुद्री वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर समुद्री वाणिज्य के संदर्भ में इससे पहले कभी भी विशेष जोर नहीं दिया गया था। चूंकि भारत अब कई बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का हिस्सा है, इसलिए समुद्री वाणिज्य में वृद्धि समुद्री सम्पर्क से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं जैसे कि बंदरगाहों एवं भीतरी इलाकों के बीच सम्पर्क, सीमा पार सम्पर्क परियोजनाओं एवं अन्य साधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

विभिन्न समुद्री क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आम तौर पर विविध क्षेत्रों के अंतर्गत वैश्विक रूप से व्यापार की जाने वाली सेवाओं, समुद्री परिवहन सेवाओं, बंदरगाह–भूमि और समुद्री मार्ग सम्पर्क सहित भीतरी इलाकों तक सम्पर्क सुनिश्चित करने इत्यादि पर गहन विचार–विमर्श किया गया है। चूंकि समुद्री उत्पादों एवं सेवाओं के व्यापार का विस्तार विविध सेक्टरों के समग्र विकास पर निर्भर करता है, इसलिए इन चर्चाओं में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं, इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आवश्यक नियामकीय एवं नीतिगत बदलावों पर प्रकाश डाला जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश के समुद्री वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्र–विशेष नीतिगत सिफारिशों को पेश किया जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय समुद्री नीति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इन सभी को एक स्थान पर समेकित करने का समय अब आ गया है।